अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)'
2.	राजस्थान में 'रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)' का प्रथम चरण
3.	एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम (ABP) की डेल्टा रैंकिंग : नीमराना देश भर में दूसरे स्थान पर
4.	7वीं UMAI राष्ट्रीय युवा मुएथाई चैंपियनशिप – 2026 में राजस्थान
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. कुशाग्र ओझा और रजत बघेल का अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम में चयन 2. 'जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान 3. शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (बाराँ) 4. मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 5. राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) का वार्षिक कारोबार 6. रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूँ खरीद लक्ष्य 7. उषा प्रियदर्शिनी : हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष 8. राजधरा सर्वे ऐप
6.	सेमीवर्स (Semiverse)
7.	भारत में कच्चा तेल का भंडार और उत्पादन
8.	भारत में घटती प्रजनन दर
9.	सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA)
10.	लिंगानुपात में असंतुलन पर उच्चतम न्यायालय
11.	मस्कट कार्य-योजना
12.	केरल में शिगेलोसिस का प्रकोप
13.	वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (Global Economic Prospects: GEP) रिपोर्ट
14.	वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index-GPI) 2026

राजस्थान परिदृश्य

राजस्थान में 'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)'

चर्चा में क्यों?

- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) एक महत्त्वाकांक्षी रेल बुनियादी ढाँचा परियोजना है, जिसका 39 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 565-567 किलोमीटर) राजस्थान से होकर गुजरता है। यह किसी भी राज्य में इस कॉरिडोर की सबसे अधिक लंबाई है।

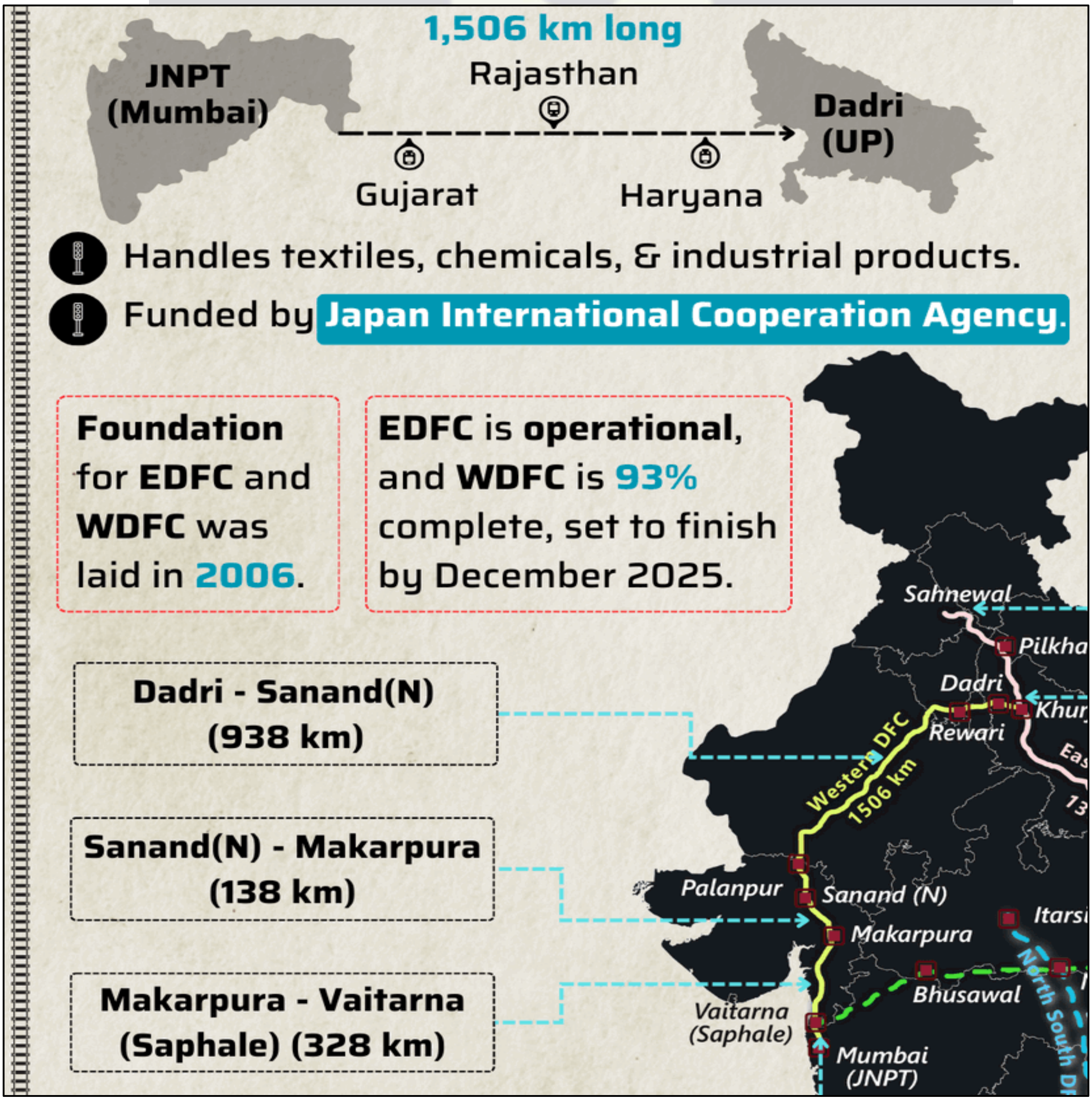

मुख्य बिन्दु:

- यह कॉरिडोर राजस्थान के कई महत्त्वपूर्ण औद्योगिक जिलों; जैसे - अलवर, जयपुर, अजमेर, सीकर, पाली और सिरोही से होकर गुजरता है।
- यह कॉरिडोर राजस्थान में आर्थिक विकास को गति देने एवं रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाएगा। साथ ही, यह कॉरिडोर राजस्थान को भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी बाजारों तक बेहतर संपर्क प्रदान करेगा।
- **अजमेर में कार्गो टर्मिनल :** अजमेर के न्यू सराधना में WDFC पर गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (GCT) स्थापित किया गया है। इस टर्मिनल में आधुनिक कार्गो हैंडलिंग अवसंरचना, वेयरहाउसिंग सुविधाएँ तथा निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे उद्योगों एवं व्यापारियों के लिए माल परिवहन अधिक तेज, सुरक्षित एवं किफायती होगा।
- यह टर्मिनल प्रति माह लगभग 40 रेक (लगभग 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष) कार्गो हैंडल करने में सक्षम है।
- **DMIC :** वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के दोनों तरफ 150 किलोमीटर का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (DMIC) के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत राजस्थान में 'खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र' और 'जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र' विकसित किए जा रहे हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (WDFC) :

- **विस्तार :** दादरी (उत्तर प्रदेश) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT), मुंबई तक।
- **कुल लंबाई :** दादरी से JNPT तक 1,506 किलोमीटर।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **क्रियान्वयन :** रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) द्वारा।
- **औसत गति :** WDFC पर मालगाड़ियों की औसत गति को 25 किमी/घंटा बढ़ाकर 70 से 100 किमी/घंटा किया गया है। इस पर 1.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर ट्रेनें 13,000 टन तक का भार ले जा सकती हैं।
- **रेल-पर-ट्रक की सुविधा :** WDFC की सबसे बड़ी विशेषता ट्रक-ऑन-ट्रेन (ToT) सेवा है। यह रेलवे की दीर्घकालिक माल परिवहन परिवर्तन रणनीति के हिस्से के रूप में बनाई गई है। इस सेवा के तहत माल से लदे ट्रकों को विशेष रूप से संशोधित फ्लैट वैगनों पर समर्पित माल ढुलाई गलियारा के माध्यम से ले जाया जाता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

राजस्थान में 'रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)' का प्रथम चरण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य राज्य में विकसित होने वाले 'रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम' के प्रथम चरण हेतु सहमति बनी।

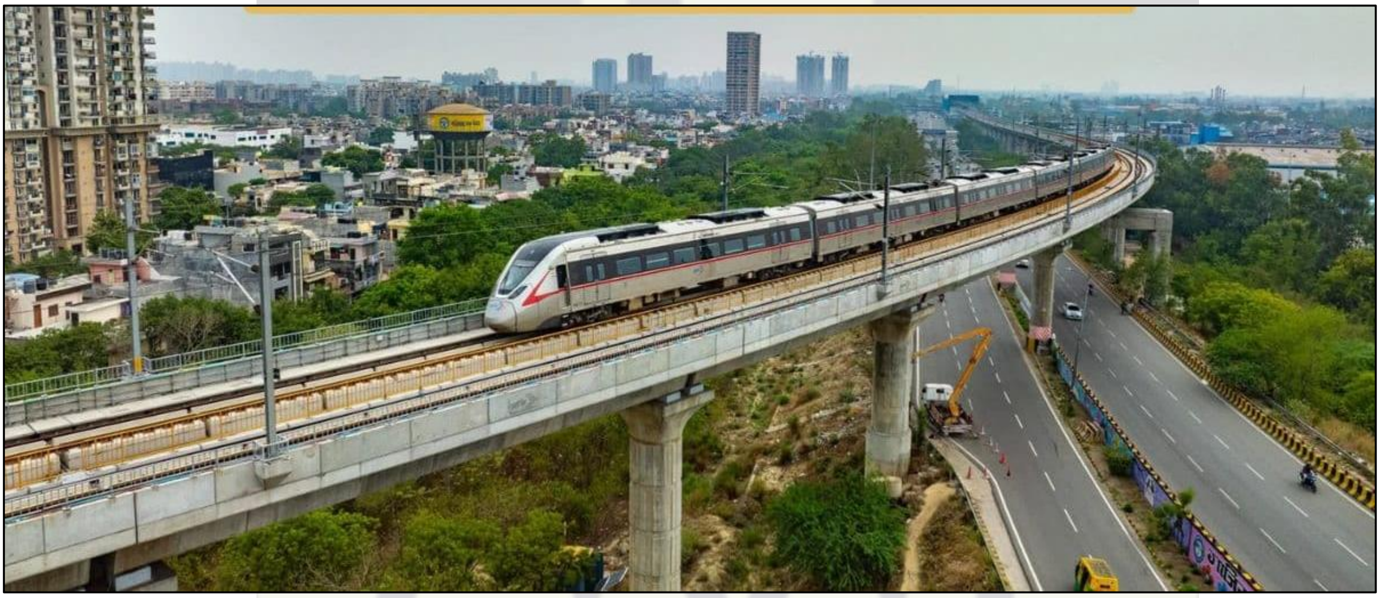

मुख्य बिन्दु:

- **RRTS का प्रथम चरण :** दिल्ली – गुरुग्राम – रेवाड़ी – शाहजहाँपुर – नीमराना – बहरोड़।
- इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत बावल (हरियाणा) से राजस्थान सीमा तक के खण्ड की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भाग हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही, राजस्थान सीमा से बहरोड़ तक के खण्ड की सम्पूर्ण लागत राजस्थान सरकार एवं उसकी संबद्ध संस्थाओं द्वारा वहन की जाएगी।
- **प्रथम चरण की कुल लंबाई :** लगभग 130 किलोमीटर होंगी तथा इसमें कुल 19 स्टेशन विकसित किए जाएँगे। इस चरण के तहत राज्य में तीन स्टेशन; शाहजहाँपुर, नीमराना तथा बहरोड़ में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

राजस्थान में RRTS परियोजना :

- रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के अन्तर्गत कुल 196 किलोमीटर लंबा नमो भारत नेटवर्क एवं 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती प्रदान करेंगे।
- राजस्थान में इस परियोजना की कुल लंबाई 91 किलोमीटर होंगी और इसमें 6 स्टेशन प्रस्तावित हैं। यह नेटवर्क 160 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्च गति जैसी सुविधाओं से लैस होगा।
- रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) सार्वजनिक परिवहन का एक अत्याधुनिक मॉडल है, जिसे विशेष रूप से NCR क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।
- इसकी ट्रेनें मेट्रो की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक गति से संचालित होती है। जहाँ मेट्रो मुख्यत: एक शहर के भीतर यात्रा का माध्यम है, वहीं RRTS निटकवर्ती शहरों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से जोड़ने का कार्य करती है।
- इस परियोजना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र; शाहजहाँपुर, नीमराना, बहरोड़, जापानी जोन, घीलोठ, KBNIR (खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन) तथा राजस्थान के उभरते लॉजिस्टिक्स हब्स लाभान्वित होंगे।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम (ABP) की डेल्टा रैंकिंग : नीमराना देश भर में दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, नीति आयोग द्वारा जारी 'एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम' (ABP) की अक्टूबर से दिसंबर, 2025 की डेल्टा रैंकिंग में कोटपुतली-बहरोड़ ज़िले का नीमराना ब्लॉक पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा।

मुख्य बिन्दु:

- साथ ही, दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा तथा जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ ब्लॉक ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
- **देश भर में प्रथम स्थान :** नागालैंड के नोकलाक ज़िले का थोनोकन्यू ब्लॉक।
- नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली इस रैंकिंग को 6 ज़ोन-वार श्रेणियों में बाँटा गया है।
- **उद्देश्य :** देश के सबसे दूरस्थ और अपेक्षाकृत अविकसित 500 ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन स्तर और सेवा वितरण (स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि) को बेहतर बनाना।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

मुख्य बिन्दु	आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP)
लॉन्च :	जनवरी, 2018	जनवरी, 2023
संचालन :	नीति आयोग द्वारा	नीति आयोग द्वारा
लक्ष्य:	देश भर के 112 जिलों में त्वरित और प्रभावी परिवर्तन लाना।	देश भर के 500 ब्लॉकों (329 जिलों) में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता लाना।
विषयवस्तु :	**पाँच विषयवस्तुओं पर केंद्रित:** स्वास्थ्य एवं पोषण। शिक्षा। कृषि एवं जल संसाधन। वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। अवसंरचना।	**पाँच विषयवस्तुओं पर केंद्रित:** स्वास्थ्य एवं पोषण। शिक्षा। कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ। अवसंरचना। सामाजिक विकास।

प्रगति संकेतक:	81	49
राजस्थान के शामिल जिले और ब्लॉक :	पाँच ज़िले – बाराँ, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही।	27 ब्लॉक - नीमराना (अलवर), सज्जनगढ़ (बाँसवाड़ा), किशनगंज (बारां), रामसर (बाड़मेर), वैर (भरतपुर), कोटड़ी (भीलवाड़ा), कोलायत (बीकानेर), केशोरायपाटन (बूँदी), निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), राजगढ़ (चूरू), रामगढ़ पचवाड़ा (दौसा), बसेड़ी (धौलपुर), जोथरी (डूँगरपुर), संगरिया (हनुमानगढ़), फतेहगढ़ (जैसलमेर), आहोर (जालौर), खानपुर (झालावाड़), शेरगढ़ (जोधपुर), मासलपुर (करौली), जायल (नागौर), रानी स्टेशन (पाली), पीपलखूंट (प्रतापगढ़), भीम (राजसमंद), गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), आबू रोड (सिरोही), पीपलू (टोंक), खेरवाड़ा (उदयपुर)

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

7वीं UMAI राष्ट्रीय युवा मुएथाई चैंपियनशिप – 2026 में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- **आयोजन :** 1 से 4 जून, 2026 तक उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गाँधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में।

मुख्य बिन्दु:

- **आयोजक :** यूनाइटेड मुएथाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

राजस्थान का प्रदर्शन :

- **कुल प्रतिभागी –** 39
- **पदक :** 9 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 14 कांस्य पदक सहित कुल 25 पदक जीते।
- **नोट :** मुदित गुप्ता मलेशिया में आयोजित होने वाली 'मुएथाई स्कूल विश्व चैंपियनशिप' के लिए राजस्थान से चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

✂️ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**कुशाग्र ओझा और रजत बघेल का अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम में चयन** ■ हाल ही में, राजस्थान के युवा क्रिकेटर कुशाग्र ओझा और रजत बघेल को BCCI ने आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम में चुना। ■ कुशाग्र ओझा भीलवाड़ा के मध्यक्रम बल्लेबाज है वहीं रजत बघेल धौलपुर के विकेटकीपर-बल्लेबाज है।
2.	**'जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान** ■ जयपुर में 'जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान का आयोजन केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर किया गया। ■ इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनसंपर्क स्थापित करके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना था।
3.	**शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (बाराँ)** ■ हाल ही में, बाराँ जिले के शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 30 वर्ष की लंबी अवधि के बाद पहली बार भालू (स्लॉथ बियर) की उपस्थिति दर्ज की गई। ■ स्लॉथ बियर जंगल में बीजों के प्रसार और दीमकों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4.	**मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना** ■ राजस्थान सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की त्वरित मदद करने वालों (Good Samaritan) को प्रोत्साहित करने के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना' चलाई जा रही है। ■ इसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (Golden Hour) के दौरान अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को ₹10,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाता है। ■ योजना के तहत जून, 2026 तक राज्य में 340 गुड सेमेरिटन सम्मानित किए जा चुके हैं।

5.	**राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) का वार्षिक कारोबार** ■ राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) ने हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग ₹1,922 करोड़ का वार्षिक कारोबार (turnover) दर्ज किया। ■ साथ ही, RSMML द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 70 करोड़ 64 लाख टन खनिजों की बिक्री की गई है। इसमें 41 लाख 95 हजार टन लाइमस्टोन, 17 लाख 65 हजार टन रॉक फॉस्फेट, 9 लाख 24 हजार टन लिग्नाइट और 1 लाख 80 हजार टन जिप्सम की बिक्री की गई। ■ राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) : ■ **स्थापना :** वर्ष 1974 ■ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राजस्थान सरकार के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन के लिए जिम्मेदार है। ■ **कंपनी का मुख्य उद्देश्य :** खनिजों के खनन में लागत प्रभावी तकनीकी नवाचारों को अपनाना और खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में विविधता लाना।
6.	**रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूँ खरीद लक्ष्य** ■ हाल ही में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूँ खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून, 2026 कर दी है। ■ राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूँ खरीद लक्ष्य 23.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन किया गया है। ■ साथ ही, राज्य सरकार की ओर से किसानों को ₹2585/क्विंटल MSP के अतिरिक्त ₹150/क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल ₹2735 का कुल भुगतान किया जा रहा है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

7.	**उषा प्रियदर्शिनी : हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष** ▪ हाल ही में, जयपुर की उषा प्रियदर्शिनी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ▪ उषा प्रियदर्शिनी मूल रूप से जयपुर की रहने वाली हैं और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री डॉ. रोहिताश शर्मा की पुत्री हैं।
8.	**राजधरा सर्वे ऐप** ▪ राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सटीक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का आकलन करने के लिए राजधरा सर्वे ऐप के माध्यम से एक विशेष डिजिटल डोर टू डोर सर्वे का आयोजन किया जाएगा। ▪ इस व्यापक डिजिटल सर्वे का मुख्य उद्देश्य राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों में OBC वर्ग को उनकी जनसंख्या और राजनीतिक स्थिति के अनुसार उचित आरक्षण देने के लिए अनुशंसाएँ तैयार करना है।

CIVIL SERVICES

राष्ट्रीय परिदृश्य

सेमीवर्स (Semiverse)

[स्रोत: PIB]

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) के विद्यार्थियों के लिए लैम रिसर्च के "सेमीवर्स" प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है।

मुख्य बिन्दु:

सेमीवर्स प्लेटफॉर्म

- यह 'डिजिटल ट्विन' आधारित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और प्रशिक्षण प्रणाली है।
- डिजिटल ट्विन भौतिक जगत की किसी वस्तु या प्रणाली का एक आभासी प्रतिरूप होता है, जो वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके उसके वास्तविक दुनिया के व्यवहार, प्रदर्शन और स्थिति को प्रतिबिंबित करता है।
- दुनिया भर के शोधकर्ता, विद्यार्थी एवं अन्य उपयोगकर्ता किसी जगह पर शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना किसी भी उपकरणों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं और दूर रहते हुए भी प्रयोग एवं अनुसंधान कार्य कर सकते हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भूगोल एवं भू-विज्ञान

भारत में कच्चा तेल का भंडार और उत्पादन

[स्रोत: AIR]

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिन्दु:

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य असम और नागालैंड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन को सुविधाजनक बनाना है।

भारत में कच्चा तेल का भंडार और उत्पादन

- भारत के पास लगभग 672.07 मिलियन टन अनुमानित कच्चे तेल का भंडार है।
- **भारत में वितरण:**
  - कच्चे तेल के भंडार मुख्यत: पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिनका हिस्सा लगभग 31% है; उदाहरण: मुंबई हाई तेल क्षेत्र।
  - **सर्वाधिक भंडार वाला राज्य:** असम (21.5%), इसके बाद राजस्थान और गुजरात का स्थान है।
- **असम में कच्चे तेल प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र:** डिगबोई (सबसे पुराना), नाहरकटिया, रुद्रसागर, लकवा और लखमानी।
- **राजस्थान:** बाड़मेर, आदि।
- **गुजरात:** अंकलेश्वर, खंभात या लुनेज क्षेत्र, कलोल, मेहसाणा, अलियाबेट, आदि।

- **उपभोग:** भारत कच्चे तेल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और तीसरा सबसे बड़ा आयातक है।

प्राकृतिक गैस का भंडार और उत्पादन

- **देश में उत्पादन:** प्राकृतिक गैस की कुल मांग का 51.4% हिस्सा देश में उत्पादित होता है। वर्ष 2024 में सकल उत्पादन 36.11 बिलियन क्यूबिक मीटर था।
- **संघटक:** इसमें मुख्य रूप से मीथेन (CH4) होती है। साथ ही प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ और गैर-हाइड्रोकार्बन गैसें (जैसे-CO2 और जल वाष्प) की कम मात्रा भी प्राप्त होती है।
- **अनुमानित भंडार:** लगभग 1,000 बिलियन क्यूबिक मीटर।
- सबसे बड़ा भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है, उसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र का स्थान है।
- **सर्वाधिक अनुमानित भंडार वाला राज्य:** असम।

UTKARSH CIVIL SERVICES

भारत में घटती प्रजनन दर

[स्रोत: THE HINDU]

चर्चा में क्यों?

- दशकों से भारतीय नीति निर्माता जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करते रहे हैं, हालांकि, हाल ही में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 हो गई है।

मुख्य बिन्दु:

नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार TFR

- भारत की कुल प्रजनन दर, यानी एक महिला द्वारा अपने जीवनकाल में औसतन जितने बच्चे पैदा किए जाएंगे, यह मानते हुए कि वह अपने प्रजनन योग्य वर्षों (15-49 वर्ष) तक जीवित रहती है, प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे गिर गई है।
- प्रतिस्थापन दर वह संख्या है जितने बच्चे एक महिला को जन्म देने पड़ते हैं ताकि बिना प्रवास के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या स्थिर बनी रहे।
- 2024 में भारत में केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य थे जिनकी कुल प्रजनन दर (TFR) 2.1 से अधिक था।
- दिल्ली में सबसे कम TFR 1.2 दर्ज की गई है, इसके बाद तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में यह 1.3 है।
- दक्षिणी राज्यों में TFR हमेशा से राष्ट्रीय औसत से कम रही है। पिछले दो दशकों में यह अंतर और भी कम हो गया है।
- मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2031 तक 1.6 से नीचे गिरने का अनुमान है।

भारत में घटती प्रजनन दर के कारण

- **देर से शादी और संतानोत्पत्ति**
- **शहरीकरण:** शहरी जीवन में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बाल देखभाल की लागत बढ़ जाती है।
- **गर्भनिरोध और परिवार नियोजन तक बेहतर पहुंच**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **शिशु एवं बाल मृत्यु दर में गिरावट:** स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता में सुधार के कारण।
- **आर्थिक कारक:** परिवार अपने जीवन की गुणवत्ता और शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कम बच्चों पर अधिक संसाधन निवेश करना पसंद करते हैं।
- **जनसांख्यिकीय संक्रमण:** भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के अंतिम चरणों से गुजर रहा है, जिसकी विशेषता कम जन्म दर, कम मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि है।

आशय

- **जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति और अंततः स्थिरीकरण**
- **बढ़ती बुजुर्ग आबादी**
- **भविष्य में श्रम बल से जुड़ी चुनौतियाँ**
- **क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन:** राज्यों में प्रजनन दर में काफी भिन्नता है, अधिकांश दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से काफी कम है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन स्तर दर्ज किए जा रहे हैं।
- इससे आंतरिक प्रवासन के पैटर्न, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधन आवंटन और श्रम बाजार की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA)

[स्रोत: THE HINDU]

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है, कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 को एक या दो राज्यों को छोड़कर, अगले वर्ष तक पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से वापस ले लिया जाएगा।

मुख्य बिन्दु:

- पूर्वोत्तर में, यह वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लागू है।

AFSPA

- इसके तहत, विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 'अशांत क्षेत्रों' में सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- **उदाहरण:** संदेह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार करना और किसी परिसर में प्रवेश/तलाशी लेना।
- **अशांत क्षेत्र की घोषणा (धारा 3):** यदि राज्यपाल, प्रशासक या केंद्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ नागरिक प्राधिकारों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है, तो वे किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कुछ हिस्से या पूरे हिस्से को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर सकते हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

समाजशास्त्र

लिंगानुपात में असंतुलन पर उच्चतम न्यायालय

[स्रोत: AIR]

चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता दोहराई है। न्यायालय ने कहा कि लिंग चयन की प्रथाएं अभी भी जारी हैं, जिससे लिंगानुपात में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।

मुख्य बिन्दु:

- **PCPNDT अधिनियम, 1994:** यह अधिनियम घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने और लिंग-चयन संबंधी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए 1994 में पारित किया गया था तथा 1996 में लागू हुआ।

लिंगानुपात में असंतुलन के कारण

- **पितृसत्तात्मक पुत्र-मोह,**
- **विवाह संबंधी रीति-रिवाज:** दहेज और पितृस्थानिकता (शादी के बाद ससुराल जाकर रहना) परंपरा,
- **प्रत्येक स्तर पर लैंगिक भेदभाव:** वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग 148 देशों में 129वें स्थान से गिरकर 131वें स्थान पर पहुंच गई, जो देश में लगातार जारी लैंगिक असमानता को दर्शाती है।
- **प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग:** प्रसव-पूर्व निदान तकनीकें लिंग-चयन और कन्या भ्रूण हत्या को आसान बनाती हैं।

- **कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव:** भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (IPC) में सख्त प्रावधान होने के बावजूद उनका प्रभावी और व्यापक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।
- जनगणना के बाल-लिंगानुपात के आँकड़ों के अनुसार, 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 945 लड़कियाँ थीं, जो 2001 में घटकर 927 और 2011 में 919 रह गईं।

सरकारी पहलें

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना:** वर्तमान में BBBP को 'मिशन शक्ति' के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- **सुकन्या समृद्धि योजना:** यह बेटियों की वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** इस योजना के तहत अब दूसरी संतान के रूप में बेटी होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

मस्कट कार्य-योजना

[स्रोत: UNO]

चर्चा में क्यों?

- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मस्कट कार्य-योजना का शुभारंभ किया।**

मुख्य बिन्दु:

मस्कट कार्य-योजना

- **उद्देश्य:** हेट-स्पीच से निपटना, नरसंहार और अन्य क्रूर अपराधों को रोकना, तथा मध्यस्थता, संवाद और स्थानीय स्तर पर शांति की स्थापना के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना।
- यह ओमान, संयुक्त राष्ट्र नरसंहार निवारण एवं सुरक्षा उत्तरदायित्व कार्यालय (UNOSAPG), और धार्मिक एवं पारंपरिक शांति निर्माताओं के नेटवर्क के नेतृत्व में शुरू की गई एक बहु-हितधारक प्रक्रिया का परिणाम है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

विज्ञान प्रौद्योगिकी

केरल में शिगेलोसिस का प्रकोप

[स्रोत: THE HINDU]

चर्चा में क्यों?

- केरल में जून, 2026 तक शिगेलोसिस (बैसिलरी पेचिश) के 85 पुष्ट मामले और 70 से अधिक संभावित मामले सामने आए हैं।

मुख्य बिन्दु:

शिगेलोसिस

- शिगेलोसिस एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो शिगेला जीनस के जीवाणुओं के कारण होता है।
- यह मुख्य रूप से आँतों को प्रभावित करता है और बेसिलरी पेचिश का कारण बनता है।
- **संचरण:** दूषित भोजन और पानी का सेवन, मल-मौखिक मार्ग के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ (Global Economic Prospects: GEP) रिपोर्ट

[स्रोत: ECONOMICS TIMES]

चर्चा में क्यों?

- नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ रिपोर्ट में भारत के लिए 2026-27 में आर्थिक संवृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया।

मुख्य बिन्दु:

- भारत के विश्व की सर्वाधिक संवृद्धि वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है।

वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ रिपोर्ट

- **जारीकर्ता:** यह विश्व बैंक समूह द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर जारी।
- **उद्देश्य:** वैश्विक आर्थिक संवृद्धि और संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण करना।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- **वैश्विक संवृद्धि अनुमान:** इसे घटाकर 2.5% (2025 में 2.9% से) कर दिया गया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद से सबसे कम आर्थिक संवृद्धि दर है।
- **बढ़ता राजकोषीय और बाहरी दबाव:** उच्च ऊर्जा सब्सिडी और कमजोर भुगतान संतुलन के कारण भारत सहित दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index-GPI) 2026

[स्रोत: AIR]

चर्चा में क्यों?

- वैश्विक शांति सूचकांक, 2026 में भारत 127वें स्थान पर रहा।

मुख्य बिन्दु:

वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2026

- **जारीकर्ता:** इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP)
- **संस्करण:** यह GPI का 20वां संस्करण है जिसमें 163 देशों को शामिल किया गया है।
- **उद्देश्य:** वैश्विक शांति और उसके आर्थिक प्रभाव को मापना।
- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष पहले स्थान पर रहा; उसके बाद न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड का स्थान है।
- **खराब प्रदर्शन करने वाले देश:** रूस इस सूची में अंतिम स्थान पर रहा, उसके बाद सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यूक्रेन और इजराइल का स्थान आता है।
- **सूचकांक तैयार करने की पद्धति:** यह तीन क्षेत्रों (सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, जारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, तथा सैन्यीकरण) के 23 संकेतकों पर आधारित है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213